

दि कौमिक पॉस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 35

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 17 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

भारत में पर्यावरण क्यों नहीं बनता चुनावी मुद्दा?

नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत का पहला आमचुनाव गर्मियों में नहीं सर्दियों में हुआ था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच। उसके बाद से अधिकांश चुनाव फरवरी के आसपास होते रहे लेकिन जब मध्यावधि चुनाव होने लगे तो सिलसिला गड़बड़ा गया। वर्ष 2004 के बाद से लोक सभा के चुनाव अप्रैल और मई के गर्म महीनों में ही हो रहे हैं। सरकारें भी पूरे पांच साल काम कर पा रही हैं इसलिए 2004 से लेकर अब तक हर पांच साल बाद गर्मियों का सीजन चुनाव का सीजन बन जाता है।

अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीजन पर सवाल उठाया तो संभवतः गर्मी के कारण चुनाव प्रचार और मतदान में होनेवाली परेशानी को देखते हुए उठाया होगा। चिलचिलाती गर्मी में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव सबको भारी पड़ता है। हालांकि 2004 के बाद से मतदान बढ़ता जा रहा है जब चुनावी महीनों में तापमान भी ऊंचा होता है। लेकिन यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या गर्मी बढ़ने से वोटिंग पर भी नकारात्मक असर पड़ता है? बहरहाल जब अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे तब गर्मी का ऐसा सितम नहीं था जैसा अब बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब धरती का तापमान बढ़ रहा है और साल दर प्रकृति के मन मिजाज में गर्मी आ रही है। इस साल तो वैसे भी अल नीनो का असर है इसलिए सर्दियों ने जहां सितम किया वहीं गर्मी भी अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही 40 डिग्री तक पहुंच गयी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्मी %रिकार्ड% कायम करेगी। मार्च के महीने में ही वैश्विक स्तर पर औसत गर्मी में 1.68 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज की जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि यह पहली बार हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़त दर्ज गयी है। धरती का यह बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन का असर है जिसके कारण पूरी धरती के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जल, जीवन सब पर इसका नकारात्मक असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण न सिर्फ खेती किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन जीने में तरह तरह का संकट पैदा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे बहुत हैं लेकिन न तो यह आम आदमी के लिए कोई मुद्दा है और न ही सरकारों या कारोबारियों के लिए चिंता का विषय। जिस %विकास%



के कारण मानव जीवन, प्रकृति, पर्यावरण और समूचे जीव जगत पर यह संकट मंडराया है उसे सीमित करने या उसको पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रयास सिर्फ रस्म अदायगी भर हैं। पर्यावरणीय बदलाव को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं। यहां से यह मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जरूर है लेकिन भारत जैसे देश में सिर्फ सरकार के स्तर पर ही इसकी चर्चा होती है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में यहां के सरकारी प्रतिनिधि जाते हैं और अपनी बात कहकर वापस आ जाते हैं। मसलन अभी पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी काॅप 28 में शामिल होने यूएई गये थे। वहां उन्होंने कहा कि अपने हेल्थ कार्ड की तरह प्रकृति के हेल्थ कार्ड के बारे में भी सोचने का समय आ गया है। वादे और दावे चाहे जितने बड़े बड़े किये जाएं लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे देशी विदेशी सम्मेलनों से जनता को कोई खास मतलब होता नहीं है। वह सिर्फ भुक्तभोगी होती है। जिन वैश्विक नीतियों के कारण पर्यावरण के सामने संकट पैदा हुआ है न तो उसको निर्धारित करने में उसकी कोई भूमिका होती है और न ही उसे यह महसूस होता है कि इन नीतियों के कारण उसका जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। भारत और चीन जैसे देश में जहां आर्थिक विकास ही इस समय इकलौता विकास बन गया है वहां अधिक से अधिक औद्योगिक माल खरीदकर संपन्न होने का दिखावा करना ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए नेता वैश्विक मंचों से पर्यावरण बचाने की चाहे जो आवाज दें लेकिन जब देश में आते हैं और चुनाव में जाते हैं तो उसी औद्योगिक आर्थिक विकास का वादा करते हैं जिसके कारण पर्यावरण और हर जीव के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। इसलिए चुनाव में नेता भी नहीं चाहते कि पर्यावरण या प्रदूषण कोई मुद्दा बने। जनता तो खैर इसे लेकर कहीं से जागरूक है ही नहीं। भारत जैसे देश में शहरी जीवन का आकर्षण इतना अधिक बढ़ा है कि गंदे से गंदे पर्यावरणीय माहौल में हम रहने के लिए तैयार हैं, बस रहनेवाली जगह किसी शहर के आसपास होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी तपिश, छह शहरों में पारा 40 डिग्री के पार

भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने के कारण मौसम शुष्क होने लगा है। इस वजह से फिर तापमान बढ़ने लगा है। इसी क्रम में मंगलवार को छह शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान धार में रिकार्ड किया गया।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो-तीन दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होने का सिलसिला बना रह सकता है। हालांकि, शाम के समय बादल छाने के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रकाश ढवले ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उससे एक द्रोणिका भी संबद्ध है। मध्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक एक द्रोणिका भी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण में नमी कम होने का सिलसिला बना रहने से मौसम शुष्क होने लगा है। इस वजह से तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि, हवाओं से कुछ नमी भी आ रही है, जिसके चलते तापमान बढ़ने के बाद शाम के समय कुछ शहरों में गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। अभी दो-तीन दिन तक मौसम शुष्क ही बना रहने की संभावना है। तापमान में कुछ और बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं। उधर, 18 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से एक बार फिर नमी बढ़ने के कारण बादल छा सकते हैं। इससे तापमान में कुछ कमी दर्ज होने लगेगी।

खतरे में हैं समुद्री तट, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं गर्मी व लू के दिनों की संख्या

मुंबई। समुद्र तटीय इलाके जलवायु परिवर्तन की मार झेलने में सबसे आगे हैं। बदलती जलवायु के चलते भूमि और समुद्र पर दोनों ही लू या हीटवेव तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दुनिया भर में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बढ़ती गर्मी के कारण बदलती जलवायु में गंभीर सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक समस्याएं सामने आ रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी।

वहीं, एक नए अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि, पिछले 20 सालों की तुलना में 1998 से 2017 के बीच तटीय इलाकों में लू या हीटवेव और समुद्र स्तर में वृद्धि की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मॉडल किए गए उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत 2025 से 2049 के बीच इन घटनाओं के पांच गुना अधिक होने की आशंका जताई गई है। अध्ययन के मुताबिक, %समवर्ती लू और चरम समुद्री स्तर% (सीएचडब्ल्यूईएसएल) कहलाने वाली ये घटनाएं तब होती हैं जब एक ही समय अवधि में एक ही तटीय स्थल पर कुछ समय के लिए लू और समुद्र के स्तर में अत्यधिक वृद्धि होती है। यद्यपि वे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं की विशेषताओं और घटनाओं पर अब तक बहुत कम शोध हुआ है। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि अध्ययनकर्ता ने 1979 से 2017 के बीच दुनिया भर में सीएचडब्ल्यूईएसएल की घटनाओं का पता लगाया और भारी उत्सर्जन जलवायु परिदृश्य (आईपीसीसी के एसएसपी5-8.5 परिदृश्य) के तहत 2025 से 2049 के बीच भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया। अध्ययनकर्ताओं ने केवल उत्तरी गोलार्ध में मई से सितंबर और दक्षिणी गोलार्ध में नवंबर से मार्च तक फैली गर्मी के मौसम में होने वाली घटनाओं को शामिल किया है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 1979 से 2017 की अवधि के दौरान दुनिया की लगभग 88 फीसदी तट रेखाओं में सीएचडब्ल्यूईएसएल घटनाएं महसूस की गईं।



मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा, अल नीनो कमजोर पड़ रहा

भारत में 2023 में मॉनसून के दौरान बारिश के सामान्य से 5.6 फीसदी कम रहने के बाद इस वर्ष बारिश का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग के मॉनसून पूर्वानुमान में बारिश को लेकर सकारात्मक बात कही गई है। अनुमान है कि 2024 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा। इसके दीर्घावधि के औसत के 106 फीसदी रहने का अनुमान है। अल नीनो कमजोर पड़ रहा है और ला नीना में सुधार हो रहा है। यह भी भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूत मॉनसूनी बारिश की एक वजह होगी। इसके साथ ही हिंद महासागर में सकारात्मक डायपोल स्थिति (एक जलवायु रुझान) और उत्तरी गोलार्ध के ऊपर सामान्य से कम हिमाच्छादित क्षेत्र भी बारिश के अनुकूल रहेगा। हालांकि बारिश का वितरण एक समान होने की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली बारिश खरीफ की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार के बावजूद यह इस फसल का अहम कारक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल घरेलू उत्पाद के जो दूसरे अग्रिम अनुमान पेश किए उनके मुताबिक खेती तथा उससे संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि 2023-24 में 0.7 फीसदी के स्तर पर रह सकती है जबकि पिछले वर्ष यह 4.1 फीसदी थी। पिछले साल अनियमित मॉनसून और अल नीनो प्रभाव के कारण इसमें आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं है। बारिश के अनियमित रुझान और सूखे जैसे हालात सामान्य फसल उत्पादन चक्र को प्रभावित कर सकते हैं और नए कीटों तथा पौधों की नई बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके विपरीत अच्छी बारिश से फसल उत्पादन और कृषि उत्पादकता दोनों में इजाफा हो सकता है। सालाना बारिश और कृषि के सकल मूल्यवर्द्धन में इजाफे के बीच स्थापित संबंध है। अच्छा मॉनसून रबी की फसल को भी फायदा पहुंचाता है क्योंकि इससे नमी बढ़ती है और जलाशयों में जल स्तर बेहतर होता है। उच्च कृषि उत्पादकता खाद्य कीमतों को सीमित दायरे में रखने में मदद करती है। पिछले कुछ समय के दौरान इसने समग्र मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर रखा है। यह ऐसे समय में हुआ है जबकि कोर मुद्रास्फीति की दर 4 फीसदी से भी कम रही है। कृषि संभावनाओं में सुधार समग्र वृद्धि को भी मदद पहुंचाएगा। इसमें उच्च उत्पादन और ग्रामीण मांग में इजाफा दोनों का योगदान होगा। उच्च उत्पादन और कम खाद्य मुद्रास्फीति भी सरकार को खाद्य उत्पादों पर से निर्यात प्रतिबंध कम करने में मदद करेगी। बार-बार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कृषि जिंसों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में हमारी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। बहरहाल, औसत से बेहतर बारिश के अनुमान के चलते हमारे नीति निर्माताओं का ध्यान उन दीर्घकालिक चुनौतियों से नहीं हटना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रही हैं। अतिरिक्त मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2023 में 365 दिनों में से 318 दिन अतिरिक्त मौसम की घटनाएं घटीं। इससे 22.1 करोड़ हेक्टेयर कृषि रकबा प्रभावित हुआ, कई जानें गईं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। यदि इसके लिए कोई बहुमुखी नीति नहीं अपनाई गई तो ऐसी घटनाओं का असर बढ़ेगा। लू के थपेड़ों और बाढ़ की घटनाओं का असर केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह आमतौर पर भी उत्पादकता और जनजीवन को प्रभावित करता है। गत वर्ष कमजोर मॉनसून के कारण जलाशयों में जलस्तर 2022 के स्तर से भी 19 फीसदी नीचे चला गया। यह 10 वर्ष के औसत स्तर से 8 फीसदी नीचे रहा। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश के आधे बड़े जलाशयों में मौजूदा जल स्तर उनकी क्षमता के 40 फीसदी से भी कम है। ऐसे में इस वर्ष बेहतर मॉनसून का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए जिससे कि भूजल का स्तर बेहतर बने और देश के प्रमुख जलाशयों में पानी रहे। बहरहाल दीर्घकालिक नीति का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि कैसे अधिक पानी बचाया जाए और कृषि क्षेत्र में पानी का इस्तेमाल कम किया जाए। हमारे जल संसाधन का अधिकांश हिस्सा कृषि में ही इस्तेमाल होता है।

रंगीन से सफेद होती मूंगा चट्टानें, वैज्ञानिकों ने की दुनिया की चौथी कोरल ब्लीचिंग घटना की पुष्टि

नई दिल्ली। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओए) के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना का सामना कर रही है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर हिन्द महासागर में तंजानिया, इंडोनेशिया तक फैली दुनिया की रंगीन मूंगा चट्टानें सफेद होती जा रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दस वर्षों में यह दूसरा मौका है जब इस तरह की घटना सामने आई है। वहीं अब तक इस तरह की चार घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। वैश्विक स्तर पर कोरल ब्लीचिंग यानी मूंगा विरंजन की पहली घटना 1980 के दशक की शुरूआत में दर्ज की गई थी। इन घटनाओं का प्रभाव सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक दर्ज किया जाता है।

एनओए और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (आईसीआरआई) ने संयुक्त रूप से वैश्विक स्तर पर हो रही इस कोरल ब्लीचिंग की घटना की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरल ब्लीचिंग यानी मूंगा विरंजन की किसी घटना को वैश्विक घटना के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब 365 दिनों के दौरान अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय तीनों महासागरों में ब्लीचिंग की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कोरल रीफ वॉच के मुताबिक 2023 के मध्य से कम से कम 53 देशों और क्षेत्रों ने अपनी प्रवाल भित्तियों में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग का अनुभव किया है, क्योंकि जलवायु में आते बदलावों की वजह से समुद्र की सतह का पानी गर्म हो गया है। इस बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरूआत से दुनिया भर के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूंगा विरंजन (कोरल ब्लीचिंग) की घटना देखी गई है।

इन क्षेत्रों में फ्लोरिडा, कैरेबियन, ब्राजील, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में मेक्सिको, अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा और कोलंबिया के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण प्रशांत के बड़े हिस्से जिनमें फिजी, वानुअतु, तुवालु, किरिबाती, समोआ और फ्रेंच पोलिनेशिया आदि शामिल हैं। इसके साथ ही कोरल ब्लीचिंग का सामना करने वाले क्षेत्रों में लाल सागर, फारस और अदन की खाड़ी के बड़े हिस्से शामिल हैं। एनओए ने तंजानिया, केन्या, मॉरीशस, सेशेल्स, ट्रोमेलिन, मैयट और इंडोनेशिया के पश्चिमी तट सहित हिंद महासागर बेसिन के अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही ब्लीचिंग की पुष्टि की है। इस बारे में एनओए की कोरल रीफ वॉच (सीआरडब्ल्यू) के समन्वयक, डॉक्टर डेरेक मंजेलो ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से जानकारी दी है कि, फरवरी 2023 और अप्रैल 2024 के बीच, सभी प्रमुख महासागरों के उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कोरल ब्लीचिंग की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई हैं। उनके मुताबिक वैश्विक महासागर के 54 फीसदी से अधिक रीफ क्षेत्रों में तापमान ब्लीचिंग के स्तर तक पहुंच गया है।

बढ़ते तापमान का दंश झेलती प्रवाल भित्तियां उन्होंने जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कि जैसे-जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। उसके साथ ही कोरल ब्लीचिंग की इन घटनाओं का होना बेहद आम होता जा रहा है। इसके साथ ही यह घटनाएं पहले से ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। उनके मुताबिक जब ब्लीचिंग की यह घटनाएं गंभीर या लंबी होती हैं, तो वे प्रवाल भित्तियों की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इससे उन समुदायों पर असर पड़ता है जो अपनी आजीविका के लिए इन मूंगा चट्टानों पर निर्भर हैं। रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से व्यापक पैमाने पर होने वाली कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं अर्थव्यवस्था, आजीविका और खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ उससे जुड़ी अन्य चीजों



को भी प्रभावित करती हैं। हालांकि इस ब्लीचिंग की वजह से हमेशा इन प्रवाल भित्तियों की मृत्यु नहीं होती। ऐसे में यदि इसकी वजह से होने वाला तनाव कम हो जाता है तो यह प्रवाल भित्तियां दोबारा ठीक हो सकती हैं। ऐसे में यह परिस्थितिकी तंत्र सम्बन्धी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना आगे भी जारी रख सकती हैं। एनओए के कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोग्राम (सीआरसीपी) के निदेशक जेनिफर कोस का कहना है कि, प्रवाल भित्तियों को लेकर जलवायु मॉडल के पूर्वानुमान वर्षों से सुझाव दे रहे हैं कि जैसे-जैसे समुद्र गर्म होगा, वैसे-वैसे ब्लीचिंग प्रभाव, उसकी आवृत्ति और परिमाण बढ़ेगा। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि यदि बढ़ते उत्सर्जन को न रोका गया तो सदी के अंत तक पूरी यह खूबसूरत प्रवाल भित्तियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। आशंका है कि अगले दो दशकों में इनकी 70 से 90 फीसदी आबादी खत्म हो सकती है।

जानिए क्या होता है कोरल ब्लीचिंग बता दें समुद्र में बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया भर में कोरल यानी प्रवाल भित्तियां जिन्हें मूंगे की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है वो अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं। ब्लीचिंग की घटना के दौरान पानी में बढ़ती गर्मी से मूंगे पर जोर पड़ता है, जिससे उनके अंदर रहने वाले सहजीवी शैवाल उनसे बाहर निकल जाते हैं। यह शैवाल कोरल को रंग और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे में इसकी वजह से आमतौर पर रंग बिरंगी दिखने वाली यह प्रवाल भित्तियां सफेद पड़ने लगती हैं, इसी को 'कोरल ब्लीचिंग' कहा जाता है। हालांकि यह सफेद प्रवाल भित्तियां मृत नहीं होती, लेकिन उनके मरने की सम्भावना सबसे अधिक होती है। अत्यधिक ब्लीचिंग अक्सर इन प्रवाल भित्तियों में बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। देखा जाए तो आज जलवायु परिवर्तन वजह से दुनिया भर में ब्लीचिंग की यह घटनाएं बेहद आम, गंभीर और व्यापक होती जा रही हैं। इसी तरह 2014 से 2017 के बीच सामने आई वैश्विक कोरल ब्लीचिंग की घटना रिकॉर्ड की अब तक की सबसे लंबी, व्यापक घटना थी, जिसने सबसे ज्यादा कोरल को नुकसान पहुंचाया था। आज यह घटनाएं उन क्षेत्रों में भी प्रवाल भित्तियों को अपना निशाना बना रही हैं, जहां पहले इनसे खतरा नहीं था। गौरतलब है कि बढ़ता तापमान और जलवायु में आता बदलाव पहले ही इन प्रवाल भित्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड-2020 रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2018 के बीच करीब 11,700 वर्ग किलोमीटर में फैली प्रवाल भित्तियां अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, जिसके लिए हम इंसान ही जिम्मेवार हैं।

वहीं दुनिया के दस क्षेत्रों में मौजूद प्रवाल भित्तियों के विश्लेषण से पता चला है कि जिस तरह से समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है उससे कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, यह प्रवाल भित्तियों को हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी ही घटना 2023 में फ्लोरिडा में देखने को मिली जब वहां आया लू का कहर बेहद घातक था। यह घटना पहले शुरू हुई और लम्बे समय तक चली, साथ ही इस घटना का असर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था।

पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों के लिए क्यों ख़ास हैं यह प्रवाल भित्तियां

एनओए ने जानकारी दी है कि उसने फ्लोरिडा में प्रवाल भित्तियों पर पड़े वैश्विक जलवायु परिवर्तन और स्थानीय तनाव के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें कोरल नर्सरी को गहरे, ठंडे पानी में भेजना और अन्य क्षेत्रों में कोरल की रक्षा के लिए सनशेड तैनात करना शामिल है। प्रवाल भित्तियां एक खूबसूरत प्रजाति है जो न केवल समुद्री परिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह हम इंसानों के लिए भी बेहद मायने रखती हैं7 देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा देशों में फैली यह भित्तियां समुद्र तल के सिर्फ 0.2 फीसदी भाग को ही कवर करती हैं, पर यह समुद्र में रहने वाली 25 फीसदी प्रजातियों को आधार प्रदान करती हैं। अनुमान है कि यह करीब 830,000 से अधिक प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं।

क्या भारत में जलवायु परिवर्तन और आतंकी गतिविधियों के बीच है कोई संबंध, रिसर्च में हुआ खुलासा

जम्मू। भारत में आतंकवादी गतिविधियों और जलवायु में आते बदलावों को लेकर किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरह से मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है, वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के स्थान को प्रभावित कर रहा है। यह अध्ययन एडिलेड और रटगर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल ऑफ एप्लाइड सिस्वोरिटी रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं।

आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है जो अनगिनत समस्याओं को जन्म दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जलवायु में आता बदलाव वैश्विक सुरक्षा, विशेषकर आतंकवाद को प्रभावित कर रहा है। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 1998 से 2017 के बीच भारत में आतंकवादी घटनाओं को लेकर एक अध्ययन किया है, जो एडिलेड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर जेरेड डिमेलो के नेतृत्व में किया गया है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भू-स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से जलवायु कारकों और आतंकवाद के बीच स्थानिक संबंधों की जांच की है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक कुछ जलवायु संबंधी कारक जैसे तापमान, वर्षा और ऊंचाई भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इस बारे में डॉक्टर डिमेलो ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से पुष्टि करते हुए कहा है कि, तापमान, बारिश और ऊंचाई आतंकवादी गतिविधियों के बदलते पैटर्न से जुड़े हैं। उनका आगे कहना है कि, शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में आबादी तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ उग्रवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में जलवायु में इतनी तेजी से बदलाव आया है कि वो अब उनके छिपने लायक नहीं रह गए हैं। इसकी वजह से उन्हें दूसरे क्षेत्रों की ओर रुख करने को मजबूर होना पड़ा है। रिसर्च के मुताबिक नए क्षेत्रों में आतंकवादियों का जाना केवल जलवायु संबंधी बदलावों की तीव्रता से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि आतंकवादी गतिविधि का यह बदलाव मौसमी भी था। ऐसे में डॉक्टर डिमेलो का कहना है कि, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों का संबोधित करना न केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि यह सीधे तौर पर



राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। गौरतलब है कि यह अध्ययन 1998 से 2017 के बीच भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित था। इस दौरान वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस ने भारत में आतंकी हमलों की 9,096 घटनाएं दर्ज की थी। डॉक्टर डिमेलो के मुताबिक इन 20 वर्षों की अवधि के दौरान भारत का औसत तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अध्ययन के दौरान बार-बार आतंकवादी हिंसा से प्रभावित हुए थे। ये क्षेत्र मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हैं। वो राज्य जो इस दौरान आतंकवाद के हॉटस्पॉट रहे उनमें जम्मू और कश्मीर, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और केरल शामिल हैं। हालांकि यह अध्ययन आतंकवादी गतिविधियों के स्थान पर केंद्रित था, लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक आंकड़े इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि इन आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अन्य मुद्दे जैसे उनके प्रशिक्षण स्थान भी जलवायु में आते बदलावों के साथ बदल रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि जलवायु में आता बदलाव भारत सहित दुनिया भर में आतंकवाद के पैटर्न को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह भारत सहित अन्य देशों में सरकारों के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों को आकार देने में मददगार साबित हो सकता है।

डॉक्टर डिमेलो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कट्टरपंथ को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे खाद्य असुरक्षा, आवास, जल एवं ऊर्जा संकट और सामाजिक असमानता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

संगम नगरी में पर्यटकों को होटलों में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

प्रयागराज । योगी सरकार संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। ऐसे में योगी सरकार महाकुंभ में 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए योगी सरकार कुंभ क्षेत्र में ही 10 हजार से अधिक की क्षमता वाली टेंट सिटी बना रही है। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से होटलों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मालूम हो कि जिला प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान 41 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया था, जिस पर योगी सरकार ने उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे।

शहर के सिविल लाइंस स्थित होटल राही इलावर्त में महाकुंभ को देखते हुए कायाकल्प का कार्य चल रहा है। राज्य पर्यटन विकास निगम प्रयागराज के वरिष्ठ प्रबंधक डीपी सिंह ने बताया कि कुल 347.41 लाख की लागत होटलों को कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें सुविधाओं का विस्तार और सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके साथ ही होटलों में फसाड लाइट का भी काम किया जा रहा है। होटल के 20 कमरों का रिनोवेशन और बेंक्रेट हॉल का रिनोवेशन के अलावा रिसेप्शन एरिया का उच्चीकरण किया जा रहा है। साथ ही होटल में किचन और पार्किंग स्थल के नवीनीकरण और उच्चीकरण कार्य प्रगति पर है। ये सभी कार्य सितंबर तक पूरे कर लिये जाएंगे। संगम नगरी में यमुना तट पर स्थित होटल राही त्रिवेणी दर्शन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पहली पसंद है क्योंकि होटल से यमुना नदी का व्यू इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ऐसे में यूपी पर्यटन विकास निगम की तरफ से एक नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य चल रहा है।